

देश की 20 यूनिवर्सिटी को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा, पूरी स्वायत्ता मिलेगी

यूजीसी सिर्फ नियामक का काम करेगी : जावड़ेकर, नवंबर से जनवरी तक चलेगी चयन प्रक्रिया, अगले सत्र से शुरू होगा काम

एसके गुप्ता | नई दिल्ली

सरकार देश की 20 यूनिवर्सिटी को अपग्रेड कर वर्ल्ड क्लास बनाने जा रही है। इनमें दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की तर्ज पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इन्हें पूरी स्वायत्ता दी जाएगी। यूजीसी की भूमिका यहां सिर्फ नियामक के तौर पर रहेगी। यानी हर काम में रोक-टोक नहीं कर पाएगी। सरकार हायर एजुकेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना चाहती है। इससे हायर एजुकेशन में गुणवत्ता भी बढ़ेगी। सत्र 2018 से इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल सुधार का ये आइडिया नीति आयोग के उस प्रस्ताव से आया है जिसमें उसने यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे संस्थानों को स्वायत्तता देने की बात कही है। प्रस्ताव में 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, प्रमुख यूनिवर्सिटी-कॉलेजों को स्वायत्तता, नियामक तंत्र में सुधार, रिसर्च के लिए अलग संस्थान तैयार करने जैसे सुझाव दिए थे। पीएम मोदी ने भी स्वाधीनता दिवस के भाषण में इसका जिक्र किया था।

केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भास्कर से बातचीत में कहा कि इस नए सिस्टम में कुलपति को यूजीसी सचिव पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सितंबर में हम इस बारे में नोटिस जारी

करेंगे, नवंबर में चयन प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी तक पूरी हो जाएगी। चयन वरिष्ठता के बजाय शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर होगा। वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और विशेषज्ञों का पैनल गठित किया जा रहा है। चुने गए हर उच्च शिक्षण संस्थान को एक-एक हजार करोड़ रु. 5 सालों में दिए जाएंगे। 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चुनी जाएंगी पर उन्हें पैसे नहीं देंगे। पर उन्हें सुधार करने की पूरी आजादी मिलेगी।

इनके अलावा श्रेष्ठ 40 यूनिवर्सिटी को भी स्वायत्तता दी जाएगी ताकि वह अपनी पसंद के कोर्स चला सकें। उन्हें फंडिंग तो यूजीसी से ही होगी पर प्रस्ताव के लिए बार-बार यूजीसी सचिव के यहां चक्कर नहीं लगाने होंगे। आईआईटी, एनआईटी को फंडिंग करने के लिए हेफा का गठन किया गया है। हेफा के जरिए ये फंड कर्ज के रूप में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा, अगर संस्थान ब्याज नहीं चुका पाया तो सरकार देगी। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी इसमें सरकार 2 हजार करोड़ रुपए निवेश करेगी और 18 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। मेधावी छात्रों को 75 हजार रुपए महीने की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ताकि गरीब छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके।